12.51 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

RUBBER (SECOND AMENDMENT) RULES 1965.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): I beg to lay on the Table a copy of the Rubber (Second Amendment) Rules, 1965, published in Notification No. G.S.R. 1397 in Gazette of India dated the 25th September, 1965, under sub-section (3) of section 25 of the Rubber Act, 1947. [*Placed in Library. See* No. LT-5128/65].

—

12.52 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House for the week commencing 15th November, 1965, will consist of:—

(1) Discussion on the present international situation and the policy of the Government of India in relation thereto on a motion to be moved by the Minister of External Affairs.

(2) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(3) Discussion on the Resolution seeking dissolution of the Indian Central Oilseeds Committee and the Indian Central Coconut Committee.

(4) Consideration and passing of the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Bill, 1965.

(5) Consideration of a motion for reference of the Patents Bill, 1965 to a Joint Committee of both Houses.

(6) Discussion on the Annual Report of the Life Insurance Corporation of India for the year ended 31st March, 1964, on a motion to be moved by Dr. L. M. Singhvi on Thursday, the 18th November, 1965 at 3 P.M.

Mr. Speaker: I would request hon. members just to mention the items which they want to be discussed and not make speeches.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Permit me to remind you, Sir, that in the last session you had admitted a motion tabled by my colleague, Shri Dwivedy and myself about the Central Vigilance Commission's first annual report. I would like that the matter may be taken up.

Mr. Speaker: Has a fresh notice been given?

Shri Hari Vishnu Kamath: We will give it.

Shri R. Ramanathan Chettiar (Karur): On a point of order, Sir. The Business Advisory Committee is composed of representatives of all parties in this House and they take a decision. But every Friday when the Minister of Parliamentary Affairs announces the business for the coming week, about half an hour to 45 minutes is taken up by those very representatives of parties who are members of the BAC, thus wasting the time of the House.

Mr. Speaker: The two things are distinguishable. The Business Advisory Committee has to allot time for those items that are brought before that committee by the Government. Only time has to be allotted to those items. But here I have allowed—of course, if the House does not want this, we may revoke it; it is for the House to decide—within not half an hour, which is too much, but not more than 10 minutes. Perhaps it might have happened that on some day it took 45 minutes. But in future I would see that only 10 minutes are taken and only the items may be mentioned about the subjects that they want to be discussed or to be brought up during the next week. That is very limited.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am sorry my hon. friend who is otherwise competent......

Mr. Speaker: About that resolution, I have received notice from two members and that resolution has been selected as well.

Shri Hari Vishnu Kamath: Then, Sir, I would request the Minister of Parliamentary Affairs that Government should make up its mind very early in this session as to what Bills listed in the bulletin of October 22nd they want to put through in this session, so that the Business Advisory Committee, yourself and the House would decide once for all the time needed for adequate discussion of those Bills.

Lastly, I may be permitted to suggest that in accordance with established parliamentary practice and recognised conventions, the minister who led the delegation recently to the Soviet Union should present a report of a work and achievements of the delegation to the House. I may be permitted to make one or two brief observations ....

Mr. Speaker: That it all; he has said that. There need not be any explanation or elaboration of it.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am sorry to say in this connection that though he has led it with such vigour and energy, I have heard in the lobbies and outside certain reports which cause me mental uneasiness that in the constitution and formation of the delegation ....

Mr. Speaker: I had just made it clear that he can speak only about the business that is to be brought before the House. This time is allotted so that members can point out what other subjects they want to be discussed and which have not been discussed. This is not a point that would be discussed in the House, unless there is any other motion brought that this might be discussed. Then too, it will have to be considered whether it is really desirable to discuss it at all, or can be discussed at all.

Shri Hari Vishnu Kamath: What about the presentation of the report?

Mr. Speaker: The report goes to the parliamentary committee.

Shri Hari Vishnu Kamath: The Nagaland delegation's report was presented to the House.

Mr. Speaker: That was a different delegation.

Shri Hari Vishnu Kamath: Was this a parliamentary delegation or not?

Mr. Speaker: I do not know, I did not send it.

Shri Hari Vishnu Kamath: The Speaker, as the keystone of the parliamentary arch must be associated with the formation of Parliamentary delegations.

Mr. Speaker: This is not the occasion to raise it.

Shri Hari Vishnu Kamath: I will raise it on some other occasion, then.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Is this important debate on international affairs going to start on Monday or later?

Shri Satya Narayan Sinha: On Monday.

Mr. Speaker: Hon. members should not take more than two minutes.

Shri Hari Vishnu Kamath: Under the rules, it is five minutes.

Mr. Speaker: Five minutes is too much.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : बताया गया कि अगले सप्ताह में विदेशी मामलों के बारे में चर्चा होगी । यह चर्चा तो व्यापक होगी । मेरा निवेदन है कि इस समय जो भारत पाक संघर्ष है उसके सम्बन्ध में एक विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए और उस पर सवाल जवाब होने चाहिए जिससे सारा मामला सामने आ सके । उसके लिए मौका निकाला जाना चाहिए ।

[श्री रामसेवक यादव]

दूसरे जो उत्तर प्रदेश और बम्बई में सूती मिलों की बन्दी हो रही है यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है और इस पर चर्चा के लिए भी मौका दिया जाए ।

तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि इस सदन के एक सदस्य श्री किरई मुसहर थे, उनका देहान्त हो गया है । उसकी सूचना यहां नहीं आई है, शायद यह जरूरी नहीं है । पर उनकी मृत्यु हो गई है । मेरा निवेदन है कि सोमवार के दिन उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाए नहीं तो यह असर होगा कि हरिजन और आदिवासी लोगों की तरफ यहां ध्यान नहीं दिया जाता ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : शायद मंत्री महोदय के ध्यान में होगा, मैंने पिछले शुक्रवार को इस तरफ ध्यान दिलाया था कि जो हमारे देश का बीड़ी वरकर का वर्ग है वह लावारिस सा है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए । मुझे आश्वासन दिया गया था कि उनका मामला इस सेशन में लिया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि उसे कब लेने वाले हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह उन्होंने कहा था ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर) : पिछले शुक्रवार को प्रधान मंत्री जी ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया था उसके कुछ ही देर बाद जब राज्य सभा में वक्तव्य दिया तो सदस्यों के आग्रह पर उन्होंने उसपर चर्चा होना स्वीकार कर लिया । मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री का वक्तव्य बड़ी असाधारण स्थिति में दिया गया है । उसके बारे में इस सदन में भी चर्चा होनी चाहिए । उसको लम्बा न टाला जाए । जितना महत्व का वह वक्तव्य है उतना ही महत्व उस पर चर्चा को देकर उस के लिए समय निकाला जाए ।

अध्यक्ष महोदय : दो दिन का वक्त फारिन एफेयर्स के लिए है उसमें यह भी आ जाएगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह उससे सम्बन्धित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उसमें आ जाएगा ।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : मेरा निवेदन है कि पंजाब की सरहद पर जो लोग रहते थे वे हाल के पाकिस्तानी हमले की वजह से उजड़ कर दूसरे शहरों में आ गए हैं । उन्हें फिर से बसाने के लिए पंजाब सरकार ने हमको आश्वासन दिए थे । पर जो लोग उजड़े हुए हैं वे दूसरी ही बात बताते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री बूटा सिंह : उनका ताल्लुक इससे है । उनके बसाने के लिए सरकार रुपया खर्च कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं पैदा होता ।

श्री बूटा सिंह : इस बारे में रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर एक बयान दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछ सकते हैं ।

3 hrs.

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर सदन और आप का ध्यान रांची में जो आग लगी थी उसके बारे में आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने नोटिस भी गत अधिवेशन में दिया था और इस बार भी दिया है और आपने खुद आश्वासन भी दिया है तो मैं चाहूंगा कि कम से कम उसके लिए कुछ समय तो निर्धारित कर दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : बिजनैस एडवाइजरी कमेटी इसको देखती है और रैकमैंड करती है। संसद्-कार्य मंत्री जवाब देंगे ।

Shri Hem Barua (Gauhati): May I submit, Sir, that there should be a separate debate on the Prime Minister's statement on Indo-Pakistan relations? "Foreign affairs" would not embrace that.

Mr. Speaker: It will embrace everything.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्री यशपाल सिंह ने पिछड़ी जमात के लोगों के बारे में जो बहस का सुझाव रखा था उस पर बहस हाउस में हुई है लेकिन वह बहस पूरी नहीं हुई है, उसकी चर्चा अधूरी है लेकिन उसका कोई जिक्र आज मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य हाउस के बिजनैस के बारे में रखा नहीं किया . .

श्री सत्य नारायण सिंह : वह जारी है ।

श्री नाथ पाई : लेकिन उस पर आगे विचार करने के लिए समय की तजवीज आपने नहीं बताई है इसलिए मैं आपके ध्यान में यह चीज लाया हूं। वह चर्चा अभी अधूरी रहती है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : अधूरी रहती है वह पूरी की जायगी।

श्री नाथ पाई : क्या उसे वे शामिल करते हैं ?

श्री राम सेवक यादव : वह एजैंडे में नहीं है।

श्री सत्य नारायन सिंह : उसे देख लेंगे उसे भी जरूर लिया जायगा ।

कुछ सवाल आपने बतला दिये । माफ़ कीजियेगा अगर मैं कहूं कि मेरे शुक्रवार को खड़े होने और जवाब देने से ेर भी बहुत सी बातें आ जाती हैं जिनसे कि मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैम्बर्स आपसे खास कर मिलने और बातचीत करने के इसलिए ख्वाहिशमंद होते हैं कि आप उनको कम ही मिल पाते हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : और मिनिस्टरों की अपेक्षा मुझसे ज्यादा मिल लेते हैं । वैसे भी मैं यहां हाउस में सब से ज्यादा हाजिर रहता हूं लेकिन अगर इस पर भी वे मुझसे संतुष्ट न हों तो मैं क्या करूं ?

अध्यक्ष महोदय : खूबसूरती भी एक क़सूर है । शेक्सपियर ने कहा था :

"Beauty provoketh thieves sooner than gold".

Shri Satya Narayan Sinha: Mr. Speaker, I shall now deal with the points raised by hon. Members. About the central Vigilance Commission you have already said, Sir, that no notice of any motion has been given by the hon. Member. I do not know whether any motion has been given. But, as you have explained, there is a sub-committee which selects out of these notices for 2½ hour discussions subjects for discussion. We can only take one motion each week. We consult the Minister concerned and fix up the date. According to the procedure, as already announced, we will be taking up one this week.

वह जो हमारे मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा तो उनकी थोड़ी ग़लतफहमी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि इसका डिस्कशन करना चाहिए लेकिन उसके बाद हम लोग जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में मिले तो वहां पर आपस में बातचीत और बहस करने के बाद यह बात तय हो गई कि फौरेन एफेयर्स

[Shri Satya Narayan Sinha]

डिबेट को जब लिया जायेगा तो उसमें यह इंडो-पाकिस्तान का भी सवाल ले लिया जायगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उस में सारी बातें नहीं आती हैं।

श्री रामसेवक यादव : उसमें वह कवर नहीं हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, यह बैठक कब हुई ? पहली बैठक में तो मैं स्वयं उपस्थित था ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं ने राज्य सभा का कहा, मालूम होता है माननीय सदस्य किसी और ध्यान में थे। हम राज्य सभा की बात कह रहे है।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Can you refer to Rajya Sabha proceedings?

श्री सत्य नारायण सिंह : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने राज्य सभा का जिक्र किया था इसलिए मैंने उसका जवाब दिया।

श्री हरि विष्णु कामत : राज्य सभा को यहां रैफर करना अनुचित है।

श्री सत्य नारायण सिंह : अब उन्होंने उसे रैफर किया मैंने जवाब दिया और हो क्या सकता है। मालूम होता है कि यहां राज्य सभा का नाम लेना मना है। उन्होंने चूंकि उसे रैफर किया था इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। (इंटरप्शंस)

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप नाराज मत होइये, आप सदा मुस्कराते रहिये। महाराज, आप के मुस्कराने से हम सब खुश रहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : जैसा रूस में करते रहे।

श्री सत्य नारायण सिंह : अब सवाल यह है कि आप ने स्वयं इस बात को तय किया है। यह बहस हुई थी इनफौरमली कई ग्रुप्स के लीडर थे। और यह सवाल वहां पर उठाया गया था। बाद में जो सब से बड़ी पार्टी है अपोजीशन में उस के लीडर ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि इस को अलग किया जाय और गवर्नमैंट की भी वही राय थी इसलिए उस कमेटी ने अपना यह फैसला दिया है कि दोनों विषयों की बहस हो। इसके वास्ते उस का समय भी हम लोग करीब दो रोज का करने जा रहे है और आप ने भी बताया कि उसका अलग अलग कोई रास्ता निकाला जाय ताकि उस पर डिस्कशन हो सके।

एक माननीय सदस्य : बीड़ी मजदूरों वाले को कब लिया जायगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं ने सम्बन्धित मिनिस्टर साहब से पूछा था वह बिल ला रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : संसदीय शिष्ट-मंडल की रिपोर्ट जिसका कि आपने नेतृत्व किया था वह कब हाउस में पेश होगी ?

श्री सत्य नारायण सिंह : इस तरह के डेलीगेशंस की कोई खास रिपोर्ट आती नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह पालिया-मैंटरी डेलिगेशन था इसकी रिपोर्ट यहां आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह पालियामैंटरी पार्टी के पास जाती है।

श्री हरि विष्णु कामत : कांग्रेस की पालियामेंटरी पार्टी में जाती है जब कि उचित तो यह है कि पालियामैंटरी डेलीगेशन की रिपोर्ट यहां पर पेश होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बस बहुत हो चुका । अब आप दोनों ही बैठ जाइये ।

श्री अ० प्र० शर्मा : रांची के बारे में नहीं बतलाया कि वह कब लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उसे देखेंगे ।

13.05 hrs.

TAXATION LAWS (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): Mr. Speaker, Sir, I beg to move*:

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Estate Duty Act, 1953, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and to provide for exemption from tax in certain cases of undisclosed income invested in National Defence Gold Bonds, 1980 be taken into consideration."

13.05½ hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Shri Tridib Kumar Chaudhuri (Berhampur): Sir, I rise to a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Let him finish his speech and then the hon. Member may raise his point of order.

Shri B. R. Bhagat: Sir, this is a short Bill intended to replace the Taxation Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 1965 which was promulgated by the President on the 19th October, 1965.

The circumstances which necessitated legislation by Ordinance have been explained in a statement circulated to hon. Members, copies of which have been placed on the Table of the House. I do not, therefore, propose to repeat what is already contained therein and shall only explain the provisions of the Bill.

The provisions of the Bill are all designed to give certain tax concessions to persons investing in the National Defence Gold Bonds, 1980 and in the two series of National Defence Loans, namely, 4½ per cent National Defence Loan, 1968 and 4¾ per cent National Defence Loan, 1972, which are currently on tap. These tax concessions are felt to be very essential for maximising investments in these Bonds and Loans. In regard to investment in the National Defence Loans, the Bill provides that resident individuals holding these loans will be entitled to receive the interest thereon without deduction of income-tax at source at the time of payment. Besides this facility to resident individuals, investment in the National Defence Loans by non-residents carries with it complete exemption of the interest from income-tax. This concession is, however, not incorporated in the Bill as it has been secured by the issue of a notification by the Government under the powers derived from section 10(4) of the Income-tax Act, 1961. That section exempts non-residents from tax on the interest on investments approved by Government and notified by it. I need hardly state that the favourable treatment to non-residents is designed to encourage the flow of funds from foreign countries into India for investment in these loans, and thereby to augment our foreign exchange resources.

Sir, the recent aggression on our territory by Pakistan and the continuing threat to our national integrity from that and other quarters and also other developments have highlighted the need for our being self-reliant to a greater extent than before in the twin spheres of defence and development. For this purpose it is vital to explore all avenues for augmenting our foreign exchange resources. Having regard to the massive proportions of this problem in the context of the present situation and with the limita-

*Moved with the recommendation of the President.